प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
12.12.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

मुख्य समाचार''

- प्रदेश सरकार ने शिमला, कुल्लू और मंडी ज़िले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का लिया निर्णय।
- राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम–2024 को अधिसूचित करने को दी मंजूरी–हिमाचलियों को दी जाएगी प्राथमिकता।
- पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश के भाजपा सांसदों ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से राज्य आपदा कोष के लिए 9 करोड़ प्रदान करने का किया आग्रह।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप–सरकार ने जश्न पर खर्च किए 25 करोड़–आउटसोर्स कर्मचारियों को चार माह से नहीं मिला वेतन।

समाचार विस्तार से.....

मंत्रिमंडल

प्रदेश सरकार ने शिमला जिले के समेज व रामपुर, कुल्लू जिले के जाओं–बागीपुल, निरमंड और मंडी जिले के टिक्कम थालू–कोट सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस पैकेज के तहत पिछले वर्ष की तरह प्रभावित परिवारों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि को बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया है। और अधिक ब्योरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता–

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में होम स्टे के संचालन पर मंत्रिमंडलीय उप–समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम–2024 को अधिसूचित करने का फैसला लिया है। नए प्रावधानों के अनुसार हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में जल विद्युत क्षेत्र पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। इन प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार 25 मेगावाट तक की उन परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक नीति का आकलन और निर्माण करेगी, जिनमें कोई प्रगति नहीं हुई है। वर्तमान में प्रदेश में इस तरह की 7 सौ से अधिक रूकी हुई परियोजनाएं हैं। मंत्रिमंडल ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना–2024 को भी मंजूरी प्रदान की। इसके तहत 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये कि वित्तीय सहायता दी जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री विधवा व एकल नारी आवास योजना–2023 के तहत गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राशि बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की गई। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक रूप से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय व चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के मध्य नर्सिंग, पैरामैडिकल, मिनिस्ट्रियल और गैर–मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के सामान्य कैडर के विभाजन को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम–2016 में संशोधन करने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा चम्बा जिले की पांगी घाटी में बिजली आपूर्ति के लिए थिरोट से किलाड़ तक 33 के.वी. की नई लाइन के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान की गई। वहीं मंत्रिमंडल ने बिलासपुर में आयोजित दो वर्ष के समारोह के सफल आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला।

सांसद भेंट

पूर्व केन्द्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में आज प्रदेश के भाजपा सांसदों राजीव भारद्वाज, कंगना रणौत, इंदु गोस्वामी और सिकंदर कुमार ने नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस दौरान केन्द्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण व तैयारी ऋण समझौते को जल्द मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्री ने जल्द ही इसके सफल क्रियान्वयन का आश्वासन दिया। इसके तहत हिमाचल को 9 सौ करोड़ रूपये का ऋण मिलेगा। उन्होंने कहा कि फरवरी 2020 में आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भौगोलिक जटिलताओं के कारण हिमाचल प्रदेश को लगभग हर वर्ष प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने करीब एक हज़ार 7 सौ 82 करोड़ रूपये की आर्थिक मदद प्रदेश को दी है।

हर्ष महाजन

राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री से चम्बा, तीसा, पांगी, किस्तवाड़, लेह को नया राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाने की मांग की। हर्ष महाजन ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने हिमाचल के ग्रामीण स्थानीय निकायों के बंधित अनुदान के रूप में 89 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा गैर सशर्त अनुदान के तौर पर प्रदेश सरकार को 81 करोड़ की राशि भी प्राप्त हुई है। वर्ष 2024–25 के लिए बंधित अनुदान की यह पहली किस्त है। इस राशि से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। हर्ष महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर माना है और प्रदेश के विकास के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी है।

ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला व एक्सहैंडल एट.द.रेट ए.आई.आर न्यूज अंडरस्कोर शिमला और यू ट्यूब चैनल ए.आई.आर शिमला न्यूज पर लॉगइन कर सकते हैं।

जयराम

पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने दो साल का जश्न मनाने में 25 करोड़ रूपये से अधिक खर्च कर दिए लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले चार महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिलासपुर में आयोजित जश्न में सरकार के पास बताने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं थी, कांग्रेस नेताओं ने केवल विपक्ष को ही कोसने का काम किया।

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं में अपने–आपको को साबित करने की होड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार व संगठन में तालमेल की कमी भी जगजाहिर हो चुकी है।

सिकंदर कुमार

केन्द्रीय विधि व न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के 11 जनवरी 2022 के निर्णय के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों को स्थाई अतिसंवेदनशील गवाह अभिसाक्ष्य केन्द्र समितियां बनाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यसभा में आज सांसद सिकंदर कुमार द्वारा इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आपराधिक संशोधन विधेयक 2018 और उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद त्वरित न्याय विशेष न्यायालयों के अंतर्गत दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना आरंभ की गई थी। इसके तहत अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस योजना के आरंभ होने के बाद हिमाचल प्रदेश को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 9 करोड़ 7 लाख रूपये जारी किए गए हैं।

राजीव भारद्वाज

केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में एक सौ 44 निजी और एक सौ 38 सरकारी अस्पताल इम्पैनल किए गए हैं। लोकसभा में सांसद राजीव भारद्वाज के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि योजना के तहत देशभर में मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 29 हज़ार 8 सौ 70 अस्पतालों का नेटवर्क स्थापित किया गया है। प्रताप राव जाधव ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 31 अक्तूबर 2024 तक हिमाचल में 13 लाख 39 हज़ार 8 सौ 90 आयुष्मान कार्ड बनाए गए और इस अवधि के दौरान 3 लाख से अधिक रोगियों पर लगभग 4 सौ 8 करोड़ रूपये की धन राशि खर्च की गई।

इंदु गोस्वामी

राज्य सभा सांसद इंदु गोस्वामी ने आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में केन्द्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से भेंट की। इस दौरान उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से कांगड़ा ज़िला के बैजनाथ मन्दिर के संरक्षण के बारे में विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि बैजनाथ मंदिर के गर्भ गृह में स्थित शिवलिंग की जलेहरी संगमरमर से बनी है और इसकी मुरम्मत का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि उचित संरक्षण द्वारा मन्दिर के शिखर से पानी का रिसाव रोक दिया गया है और चालू वित वर्ष के दौरान मंदिर में टैगिंग व अन्य विकास कार्य करवाने के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि चंबा ज़िले के भटियात विधानसभा क्षेत्र में अगले तीन वर्षों के दौरान सड़क, विद्युत, पेयजल व सिंचाई व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए करीब एक हज़ार करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने आज शहीद आशीष थापा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घटासनी के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। पठानिया ने कहा कि ज़िले में लोगों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान चंबा–चुवाड़ी सुरंग निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

मुख्य समाचार एक बार फिर'

- प्रदेश सरकार ने शिमला, कुल्लू और मंडी ज़िले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का लिया निर्णय।
- मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम–2024 को अधिसूचित करने को दी मंजूरी–हिमाचलियों को दी जाएगी प्राथमिकता।
- पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश के भाजपा सांसदों ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से राज्य आपदा कोष के लिए 9 करोड़ प्रदान करने का किया आग्रह।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप–सरकार ने जश्न पर खर्च किए 25 करोड़–आउटसोर्स कर्मचारियों को चार माह से नहीं मिला वेतन।